IJARASEM

ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management

Volume 10, Issue 6, November 2023

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 6.551

+91 9940572462 +91 9940572462 ijarasem@gmail.com www.ijarasem.com

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 6, November 2023 |

वैश्विक अर्थव्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय बैंक का योगदान

DR. OMPRAKASH MEENA

ASSISTANT PROFESSOR, EAFM , SPNKS GOVT. PG COLLEGE, DAUSA, RAJASTHAN, INDIA

सार

इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निमाण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। यह एक अग्रणी विकास संस्थान है, जो विकासशील देशों में गरीबी से लड़ने तथा सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिये ऋण, गारण्टी, जोखिम प्रबन्धन उत्पादों और विश्लेषणात्मक तथा सलाहकार सेवाएँ देने का काम करता है।

परिचय

विश्व बैंक विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निमाण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक समूह पाँच अन्तर राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन, डी॰ सी॰ में है।[2] स्थापना 1944 में हुई ।

विश्व बैंक (world bank) समूह से जुड़ी सामान्य जानकारी

अन्तरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (International Bank for Reconstruction and Development-IBRD) और अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन (Bretton Woods Conference) के दौरान हुई थी। ये दोनों संस्थाये ब्रेटन वुड्स की संस्था है !ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन (United Nations Monetary and Financial Conference) के रूप में जाना जाता है। से 22 जुलाई, 1944 तक 44 देशों के प्रतिनिधि इस सम्मलेन में शामिल हुए थे। इसका तात्कालिक उद्देश्य द्वितीय विश्वयुद्ध और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना था।[1,2,3]

- अन्तरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है।
- इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC (पूर्व में District of Colombia) में है।
- विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है और यह कई संस्थाओं का समूह है। इसीलिये इसे विश्व बैंक समूह (World Bank Group) भी कहा जाता है।
- वर्तमान में विश्व बैंक में 189 देश सदस्य हैं।। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिये किसी भी देश को पहले अन्तरराष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना ज़रूरी होता है।

दोनों में अन्तर

विश्व बैंक नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिये ऋण देता है, जबकि अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल नीति सुधार कार्यक्रमों के लिये ही ऋण देता है। इन दोनों संस्थाओं में एक अंतर यह भी है कि विश्व बैंक केवल विकासशील देशों को ऋण देता है, जबकि अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संसाधनों का इस्तेमाल निर्धन राष्ट्रों के साथ-साथ धनी देश भी कर सकते हैं।

- इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निमाण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है।
- यह एक अग्रणी विकास संस्थान है, जो विकासशील देशों में गरीबी से लड़ने तथा सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिये ऋण, गारण्टी, जोखिम प्रबन्धन उत्पादों और विश्लेषणात्मक तथा सलाहकार सेवाएँ देने का काम करता है।
- इसके सदस्य देश संयुक्त रूप से इसकेलिये ज़िम्मेदार होते हैं कि कैसे इसका वित्तपोषण किया जाता है और इसका पैसा कैसे खर्च किया जाता है।
- विश्व बैंक का प्रयास सतत गरीबी में कमी के उद्देश्य से सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों तक पहुँचने पर केन्द्रित हैं।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 6, November 2023 |

विश्व बैंक समूह में शामिल संस्थान

विश्व बैंक समूह निम्नलिखित पाँच अन्तरराष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को आर्थिक-वित्तीय सहायता और वित्तीय सलाह देता है:

1. पुनर्निर्माण और विकास के लिये अन्तरराष्ट्रीय बैंक (International Bank for Reconstruction and Development-IBRD)

IBRD की स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी और वर्तमान में इसके 189 सदस्य हैं। IBRD का उद्देश्य मध्यम विकास वाले देशों और ऋणग्रस्त गरीब देशों में ऋण, गारण्टी और गैर-उधार सेवाओं के माध्यम से सतत् विकास को बढ़ावा देना है, जिसमें विश्लेषणात्मक और सलाहकार सेवाएँ शामिल हैं। IBRD उन सदस्य देशों के स्वामित्व में है जिनकी मतदान शक्ति देश की सापेक्ष आर्थिक शक्ति के आधार पर इसकी पूँजी सदस्यता से जुड़ी हुई है। IBRD दुनिया के वित्तीय बाज़ारों से अपना अधिकांश धन जुटाता है और वर्ष 1959 से इसने AAA रेटिंग बनाए रखी है। IBRD और IDA मिलकर विश्व बैंक का स्वरूप लेते हैं, जो विकासशील देशों की सरकारों को वित्तपोषण, नीति सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह विश्व बैंक के परिचालन खर्चों को वहन करता है तथा बेहद गरीब देशों के लिये IDA को धन प्रदान करता है।

2. अन्तरराष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation-IFC)

वर्ष 1956 में स्थापित IFC 184 सदस्य देशों के स्वामित्व में है, जो सामूहिक रूप से नीतियों को निर्धारित करता है। यह 100 से अधिक विकासशील देशों में उभरते बाज़ारों में कम्पनियों और वित्तीय संस्थानों को रोजगार सृजित करने, कर राजस्व जुटाने, कॉर्पोरेट प्रशासन और पर्यावरण प्रदर्शन में सुधार करने तथा उनके स्थानीय समुदायों में योगदान करने में सहायता देता है। यह विकासशील देशों में विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर केन्द्रित सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है। IFC अन्तरराष्ट्रीय पूँजी बाजार में ऋण दायित्वों को पूरा करने के माध्यम से लगभग सभी ऋण गतिविधियों के लिये धन जुटाता है। वर्ष 1989 के बाद से IFC ने अपनी AAA रेटिंग बनाए रखी है। यह आमतौर पर 7 से 12 साल की परिपक्वता वाले व्यवसायों और निजी परियोजनाओं को ऋण देता है। इसके द्वारा किये जाने वाले निवेशों के लिये समान ब्याज दर की नीति नहीं है। IFC अन्तरराष्ट्रीय लेन-देन के जोखिम को कम करने के लिये अपने वैश्विक व्यापार वित्त कार्यक्रम के माध्यम से 80 से अधिक देशों में 200 से अधिक अनुमोदित बैंकों के व्यापार भुगतान दायित्वों की गारण्टी देता है।

3. अन्तरराष्ट्रीय विकास संघ (International Development Association-IDA)

IDA की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी और वर्तमान में इसके 173 देश सदस्य हैं। IDA विश्व बैंक का वह हिस्सा है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करता है। 173 शेयरधारक देशों द्वारा प्रबंधित IDA का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, असमानताओं को कम करना और लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार के लिये अनुदान प्रदान करना है। यह दुनिया के 75 सबसे गरीब देशों में बुनियादी सामाजिक सेवाओं हेतु सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, इनमें से 39 अफ्रीका में हैं। IDA रियायती शर्तों पर ऋण देता है अर्थात यह शून्य या बहुत कम ब्याज शुल्क लेता है और पुनर्भुगतान 30 से 38 वर्ष तक किया जा सकता है, जिसमें 5 से 10 साल की छूट अवधि भी शामिल है। यह समानता, आर्थिक विकास, रोज़गार सृजन, उच्च आय और बेहतर जीवन स्थितियों का समर्थन करते हुए सहायता प्रदान करता है। प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और स्वच्छ पानी, कृषि, व्यापार जलवायु सुधार, बुनियादी ढाँचा और संस्थागत सुधारों के लिये भी IDA सहायता करता है।

4. निवेश विवादों के निपटारे के लिये अन्तरराष्ट्रीय केंद्र (International Centre for Settlement of Investment Disputes-ICSID)[4,5,6]

वर्ष 1966 में स्थापित ICSID एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ICSID अभिसमय एक बहुपक्षीय संधि है जिसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों द्वारा तैयार किया गया है ताकि बैंक के निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों के सुलह और मध्यस्थता के लिये सुविधाएँ प्रदान करना है। अधिकांश देशों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेश संधियों और कई निवेश कानूनों और अनुबंधों में निवेशक-राज्य विवाद निपटान के लिये एक मंच के रूप में ICSID को मान्यता दी है। इसका नेतृत्व महासचिव द्वारा किया जाता है जो कार्यवाही के लिये तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। इसके महासचिव को पंचाट न्यायाधिकरण या सुलह आयोग का गठन करने का अधिकार है। अधिकांश मामलों में न्यायाधिकरण में तीन मध्यस्थ होते हैं: निवेशक द्वारा नियुक्त, राज्य द्वारा नियुक्त और दोनों पक्षों के समझौते द्वारा नियुक्त।

5. बहुपक्षीय निवेश गारण्टी एजेंसी (Multilateral Investment Guarantee Agency-MIGA)

12 अप्रैल, 1988 को विश्व बैंक समूह के नए सदस्य के रूप में MIGA की स्थापना की गई। कानूनी तौर पर अलग और आर्थिक रूप से स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यवसाय के लिये खोली गई MIGA में 179 देश सदस्य हैं। MIGA को विकासशील देशों में गैर-वाणिज्यिक जोखिमों के खिलाफ निवेश बीमा के सार्वजनिक और निजी स्रोतों के पूरक के लिये बनाया गया था। यह ऋणदाताओं और निवेशकों को युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देना है ताकि आर्थिक विकास में मदद मिल सके, गरीबी को कम किया जा सके और लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। MIGA का गठन विकासशील देशों में गैर-वाणिज्यिक जोखिमों के खिलाफ निवेश और बीमा

के सार्वजनिक और निजी स्रोतों के पूरक के तौर पर किया गया था। इन जोखिमों में मुद्रा की अनिश्चितता और हस्तान्तरण प्रतिबन्ध; सरकार का विघटन; युद्ध, आतंकवाद और नागरिक गड़बड़ी; अनुबन्ध का उल्लंघन तथा वित्तीय दायित्वों के निर्वहन से भटकाव की स्थिति आदि शामिल हैं।

विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक मण्डल

विश्व बैंक समूह के चार संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यकारी निदेशकों के चार बोर्ड हैं: इण्टरनेशनल बैंक फ़ॉर रिकंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपमेंट (IBRD), अन्तरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (IDA), अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) और बहुपक्षीय निवेश गारण्टी एजेंसी (MIGA)।

- इन बोर्डों में काम करने वाले कार्यकारी निदेशक आमतौर पर समान होते हैं।
- कार्यकारी निदेशकों के ये बोर्ड विश्व बैंक समूह के सामान्य संचालन के लिये उत्तरदायी हैं और सदस्यों का प्रतिनिधित्व बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स द्वारा किया जाता है।
- बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स उन्हें सौंपी गई सभी शक्तियों का उपयोग करते हैं।
- इन बोर्ड्स में 24 कार्यकारी निदेशक होते हैं और एक अध्यक्ष होता है।
- हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन के अधिकारी डेविड मालपास को विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के तौर पर चुना गया।
- विश्व बैंक के कार्यकारी बोर्ड ने आम सहमति से उनका चयन किया।
- विश्व बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक इसके अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित करता है।
- अमेरिका विश्व बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक है और यही कारण है कि अब तक इसके सभी अध्यक्ष अमेरिकी ही रहे हैं।

विश्व बैंक समूह की सदस्यता

- IBRD के आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट के तहत बैंक का सदस्य बनने के लिये किसी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में शामिल होना अनिवार्य है।
- IBRD की सदस्यता मिलने पर ही IDA, IFC और MIGA की सदस्यता मिलती है।
- ICSID में सदस्यता IBRD के सदस्यों के लिये उपलब्ध होती है, किंतु जो IBRD के सदस्य नहीं हैं, लेकिन पार्टी ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) के सदस्य हैं, उन्हें ICSID प्रशासनिक परिषद के आमंत्रण पर अपने सदस्यों के दो-तिहाई वोट का समर्थन मिलने पर ही सदस्यता दी जाती है।

विश्व बैंक समूह और भारत

- भारत ब्रेटन वुड्स में किये गए समझौतों के मूल हस्ताक्षरकर्त्ताओं में से एक था, जिसने इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपमेंट (IBRD) और अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)) की स्थापना की।
- भारत वर्ष 1956 में IFC और 1960 में IDA के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल था।
- भारत जनवरी वर्ष 1994 में MIGA का सदस्य बना।

भारत ICSID का सदस्य नहीं है। इसके पीछे भारत का यह तर्क है कि ICSID कन्वेंशन निष्पक्ष नहीं है और इसके नियम विकसित देशों के पक्ष में झुके हुए हैं। ICSID में केन्द्रीय अध्यक्ष विश्व बैंक का अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष मध्यस्थों की नियुक्ति करता है। यदि मध्यस्थता से जुड़े निर्णय सन्तोषजनक नहीं होते है, तो असन्तुष्ट पक्ष एक पैनल से अपील करता है जिसे ICSID द्वारा ही गठित किया जाता है। इसमें भारतीय न्यायालयों द्वारा निर्णय की समीक्षा किये जाने की कोई अधिकार नहीं है, भले ही उसका यह निर्णय (Award) सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो।

- वर्ष 1949 में भारतीय रेल को ऋण देने के साथ IBRD द्वारा भारत को ऋण देने की शुरुआत हुई तथा वर्ष 1959 में भारत में IFC और वर्ष 1961 में IDA द्वारा पहला निवेश एक राजमार्ग निर्माण परियोजना पर किया गया।
- 1950 के दशक के दौरान भारत हेतु विश्व बैंक के ऋण का एकमात्र स्रोत IBRD था। दशक के अंत तक भारत की बढ़ती ऋण समस्या विश्व बैंक समूह के सॉफ़्ट लोन से जुड़े IDA के लॉञ्च (launch) में एक महत्त्वपूर्ण कारक बनी।
- 1960 के दशक के अन्त में अमेरिका ने अपने द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम में तेजी से कटौती की, जो उस समय भारत के बाहरी संसाधनों का सबसे बड़ा स्रोत था। तब से ही विश्व बैंक आधिकारिक तौर पर दीर्घकालिक वित्त के सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरा।
- 1960 और 1970 के दशक के दौरान IDA ने विश्व बैंक द्वारा दिये गए कुल ऋण का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा भारत को दिया। इस प्रकार IDA से अब तक का सबसे बड़ा ऋण प्राप्तकर्ता भारत बना और यह राशि कुल दिये गए सभी ऋणों के 2/5 हिस्से के बराबर थी।

- चीन वर्ष 1980 में विश्व बैंक में शामिल हुआ और उसने सीमित IDA संसाधनों पर अपनी दावेदारी भी जताई।
- अफ्रीका के बिगड़ते आर्थिक हालात और भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन से IDA में भारत की ऋण हिस्सेदारी तेज़ी से कम होने लगी।
- 1980 के दशक के दौरान विश्व बैंक ने नीतियों में सुधार और आर्थिक उदारीकरण पर ज़ोर दिया। यह भारत में बुरे दौर से गुज़र रहे सार्वजनिक संस्थानों को ऋण देता रहा और भारत की बंद अर्थव्यवस्था की आलोचना को लेकर मौन साधे रहा।
- वर्ष 1991 के व्यापक आर्थिक संकट के बाद परिस्थितियों में तेजी से बदलाव आया। इसके बाद संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (Structural Adjustment Program-SAP) के अंतर्गत ऋण देने के लिये विश्व बैंक के लिये भारत महत्त्वपूर्ण देश बन गया, क्योंकि उसने वित्त, कराधान और निवेश तथा बिज़नेस आदि क्षेत्रों में नीतिगत सुधारों के लिये सहमति जताई थी।
- भारत को वर्तमान में मिश्रित देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे निम्न मध्यम-आय से मध्यम-आय में जाने वाले देश के रूप में परिभाषित किया गया है तथा यह IDA और IBRD दोनों से ऋण लेने के लिये योग्य देश है।
- विश्व बैंक के IBRD से सबसे अधिक ऋण लेने वाला देश भारत है। 2015 से 2018 के बीच विश्व बैंक ने भारत को लगभग $ 10.2 बिलियन का ऋण दिया है।
- विश्व बैंक समूह ने 2019-22 की अवधि में भारत के लिये 25-30 बिलियन डॉलर की योजनाओं हेतु ऋण प्रतिबद्धताओं को मंजूरी दी है।[7,8,9]

विश्व बैंक में सुधार

- विश्व बैंक पर यह आरोप लगता रहा है कि यह अपने SAP के ज़रिये विश्व में पूंजीवाद के उद्देश्यों को पूरा करता है और इसमें अमीर देशों का वर्चस्व रहता है।
- यह SAP 'मुक्त बाज़ार' हेतु आर्थिक नीति में सुधारों का एक समूह है जो विश्व बैंक द्वारा विकासशील देशों पर ऋण प्राप्ति की शर्त के रूप में लागू किया है।
- यह तर्क दिया जाता है कि SAP नीतियों ने स्थानीय और वैश्विक दोनों ही स्थितियों में अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ाया है।
- उभरती हुई नई आर्थिक शक्तियों, विशेष रूप से भारत और चीन तथा दुनिया के कुछ अन्य एशियाई एवं कुछ लैटिन अमेरिकी देशों को विश्व बैंक में उचित स्थान और भूमिका दी जानी चाहिये।
- विश्व बैंक अपने आपको बदलती विश्व व्यवस्था के अनुकूल ढालने में विफल रहा है, इसीलिये तेज़ी से आगे बढ़ रही भारत और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं ने एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) की स्थापना की है।
- विश्व बैंक में सुधार वर्तमान विश्व व्यवस्था को पुनर्जीवित करने और बढ़ती शक्तियों और विकासशील देशों को इस संस्था में एक सार्थक आवाज़ देने के हिस्से के रूप में बेहद आवश्यक हैं।

भारत के भविष्य को लेकर विश्व बैंक का रुख

1.4अरब की जनसंख्या और विश्व की पाँच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत की हाल की संवृद्धि तथा इसका विकास वर्तमान समय की अत्यंत उल्लेखनीय सफलताओं में से हैं। आज फार्मा, इस्पात, सूचना तथा अंतरिक्ष-संबंधी प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की पहचान विश्व-स्तर पर है तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी आवाज़ माना जाता है, जो इसके विशाल आकार और संभावनाओं के अनुरूप है।

भारत में बड़े बदलाव आ रहे हैं, जिनसे इसके लिये 21वीं सदी का मज़बूत देश बनने के नए-नए अवसर पैदा हो रहे हैं। भारत विश्व का सबसे विशाल और अत्यंत युवा श्रमशक्ति वाला देश है। साथ ही देश में शहरीकरण की तीव्र प्रक्रिया चल रही है और प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ लोग रोज़गार तथा अवसरों की तलाश में कस्बों और शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। यह इस सदी का विशालतम ग्रामीण और शहरी प्रवासन है।

इन बदलावों की वज़ह से भारत एक ऐसे मोड़ पर पहुँच गया है, जहाँ यह देखना बेहद ज़रूरी होगा कि भारत अपनी श्रमशक्ति की उल्लेखनीय सामर्थ्य का विकास किस प्रकार करता है और अपने बढ़ते हुए शहरोंव कस्बों की संवृद्धि के लिये किस तरह की नई योजनाएँ तैयार करता है। इन्हीं सब बातों से आने वाले समय में देश और इसके निवासियों का भविष्य निर्धारित होगा।

विचार-विमर्श

विश्व अर्थव्यवस्था या वैश्विक अर्थव्वस्था (global economy) से प्रायः विश्व के सम्पूर्ण देशों की अर्थव्यवस्था पर आधारित अर्थव्यवस्था का बोध होता है। इस प्रकार वैश्विक अर्थव्वस्था को 'विश्व समाज' की अर्थव्वस्था कह सकते हैं जबकि राष्ट्रीय अर्थव्वस्थाएँ 'स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं' कहलायेंगी।

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 6, November 2023 |

विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) तथा वैश्विक आर्थिक विकास में हिस्सेदारी के अनुसार विश्व की २५ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ ये हैं-

GDP (नॉमिनल) के आधार पर २५ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ और उनकी अधिकतम जीडीपी (मिलियन US$ में)[1]

रैंक	देश	मान (USD$)	किस वर्ष में अधिकतम
—	विश्व	87,504,567	2018
1	संयुक्त राज्य अमेरिका	20,412,870	2018
—	ई॰ यू॰	19,669,743	2018
2	चीन	14,092,514	2018
3	जापान	6,203,213	2012
4	जर्मनी	4,211,635	2018
5	यूनाइटेड किंगडम	3,075,538	2007
6	फ्रांस	2,937,321	2008
5	भारत|3,5800,000	2018	
8	ब्राज़ील	2,613,859	2011
9	इटली	2,402,062	2008
10	रूस	2,297,125	2013
11	कनाडा	1,842,627	2013
12	दक्षिण कोरिया	1,693,246	2018
13	स्पेन	1,642,765	2008
14	ऑस्ट्रेलिया	1,566,533	2012
15	मेक्सिको	1,314,390	2014
16	इण्डोनेशिया	1,074,966	2018
17	तुर्की	950,328	2013
18	नीदरलैंड	945,327	2018
19	साँचा:Country data सउदी अरब	756,350	2014
20	स्विट्ज़रलैंड	741,688	2018
21	अर्जेंटीना	642,464	2015
22	पोलैंड	614,190	2018
23	ताइवान	613,295	2018
24	स्वीडन	600,771	2018
25	ईरान	577,214	2011

GDP (PPP) के आधार पर २५ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ और उनकी अधिकतम जीडीपी (मिलियन US$ में)[2]

रैंक	देश	मान (USD$)	किस वर्ष में अधिकतम
—	World	134,981,037	2018
1	चीन	25,238,563	2018
—	ई॰ यू॰	21,998,468	2018
2	संयुक्त राज्य अमेरिका	20,412,870	2018
3	भारत	10,385,432	2018
4	जापान	5,619,492	2018
5	जर्मनी	4,373,951	2018
6	रूस	4,168,884	2018
7	इण्डोनेशिया	3,492,208	2018
8	ब्राज़ील	3,388,962	2018
9	यूनाइटेड किंगडम	3,028,566	2018
10	फ्रांस	2,960,251	2018
11	मेक्सिको	2,571,680	2018
12	इटली	2,399,825	2018
13	तुर्की	2,320,641	2018
14	दक्षिण कोरिया	2,138,242	2018
15	स्पेन	1,864,105	2018
16	कनाडा	1,847,081	2018
17	साँचा:Country data सउदी अरब	1,844,751	2018
18	ईरान	1,749,428	2018
19	ऑस्ट्रेलिया	1,312,534	2018
20	थाईलैण्ड	1,310,573	2018
21	मिस्र	1,292,745	2018
22	ताइवान	1,234,862	2018
23	पोलैंड	1,193,112	2018
24	नाईजीरिया	1,168,399	2018
25	पाकिस्तान	1,141,210	2018

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 6, November 2023 |

सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) के अनुसार विश्व की २० सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ[10,11]

निम्नलिखित सारणी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार है।[3]

रैंक	1980	1985	1990	1995	2000	2020	2010	2015	2020
1	साँचा:Ind	साँचा:Ind	साँचा:Ind	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका	साँचा:Ind	संयुक्त राज्य अमेरिका	साँचा:Ind
2	साँचा:Country data सोवियत संघ	साँचा:Country data सोवियत संघ	जापान	जापान	जापान	जापान	चीन	चीन	चीन
3	जापान	जापान	साँचा:Country data सोवियत संघ	जर्मनी	जर्मनी	जर्मनी	जापान	जापान	जापान
4	साँचा:Country data पश्चिमी जर्मनी	साँचा:Country data पश्चिमी जर्मनी	साँचा:Country data पश्चिमी जर्मनी	फ्रांस	यूनाइटेड किंगडम	यूनाइटेड किंगडम	जर्मनी	जर्मनी	जर्मनी
5	फ्रांस	फ्रांस	फ्रांस	यूनाइटेड किंगडम	फ्रांस	चीन	यूनाइटेड किंगडम	यूनाइटेड किंगडम	भारत
6	यूनाइटेड किंगडम	यूनाइटेड किंगडम	यूनाइटेड किंगडम	इटली	इटली	फ्रांस	फ्रांस	फ्रांस	फ्रांस
7	इटली	इटली	इटली	ब्राज़ील	चीन	इटली	इटली	ब्राज़ील	यूनाइटेड किंगडम
8	चीन	कनाडा	कनाडा	चीन	ब्राज़ील	कनाडा	ब्राज़ील	इटली	ब्राज़ील
9	कनाडा	चीन	ईरान	स्पेन	कनाडा	स्पेन	रूस	रूस	इटली
10	मेक्सिको	भारत	स्पेन	कनाडा	मेक्सिको	दक्षिण कोरिया	भारत	भारत	रूस
Rank	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020
11	स्पेन	ब्राज़ील	ब्राज़ील	ईरान	स्पेन	ब्राज़ील	स्पेन	कनाडा	कनाडा
12	ब्राज़ील	मेक्सिको	चीन	दक्षिण कोरिया	दक्षिण कोरिया	मेक्सिको	कनाडा	स्पेन	दक्षिण कोरिया
13	भारत	ऑस्ट्रेलिया	भारत	मेक्सिको	ईरान	भारत	ऑस्ट्रेलिया	ऑस्ट्रेलिया	ऑस्ट्रेलिया
14	नीदरलैंड	स्पेन	ऑस्ट्रेलिया	नीदरलैंड	भारत	रूस	दक्षिण कोरिया	दक्षिण कोरिया	स्पेन

15	ऑस्ट्रेलिया	ईरान	नीदरलैंड	ऑस्ट्रेलिया	नीदरलैंड	ऑस्ट्रेलिया	मेक्सिको	मेक्सिको	मेक्सिको
16	साँचा:Country data सउदी अरब	नीदरलैंड	मेक्सिको	भारत	रूस	नीदरलैंड	नीदरलैंड	तुर्की	इण्डोनेशिया
17	स्वीडन	स्वीडन	दक्षिण कोरिया	स्विट्ज़रलैंड	ऑस्ट्रेलिया	ईरान	तुर्की	नीदरलैंड	नीदरलैंड
18	बेल्जियम	साँचा:Country data सउदी अरब	स्विट्ज़रलैंड	रूस	स्विट्ज़रलैंड	तुर्की	इण्डोनेशिया	इण्डोनेशिया	तुर्की
19	स्विट्ज़रलैंड	स्विट्ज़रलैंड	स्वीडन	बेल्जियम	ताइवान	स्विट्ज़रलैंड	स्विट्ज़रलैंड	साँचा:Country data सउदी अरब	स्विट्ज़रलैंड
20	ईरान	दक्षिण कोरिया	तुर्की	अर्जेंटीना	अर्जेंटीना	स्वीडन	ईरान	स्विट्ज़रलैंड	साँचा:Country data सउदी अरब

परिणाम

अर्थशास्त्र में, आर्थिक वैश्वीकरण वैश्वीकरण का अर्थशास्त्र है ।[1] यह माल और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन से संदर्भ है। इसने आर्थिक विकास किया है। [2][3] वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ हैं, और इन्हें प्रतिष्ठित किया जा सकता है।[4] IMF और WTO दुनिया भर में वैश्वीकरण की आर्थिक नीतियों का निर्धारण करते हैं।[4]

जबकि आर्थिक वैश्वीकरण ने विकासशील देशों में आय और आर्थिक विकास में वृद्धि की है और विकसित देशों में उपभोक्ता मूल्य में कमी आई है, यह विकासशील और विकसित देशों के बीच शक्ति संतुलन को भी बदलता है। [3]

प्रभाव

आर्थिक विकास और गरीबी में कमी

वैश्वीकरण के त्वरण के बाद वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास में तेजी आई और गरीबी में कमी आई।

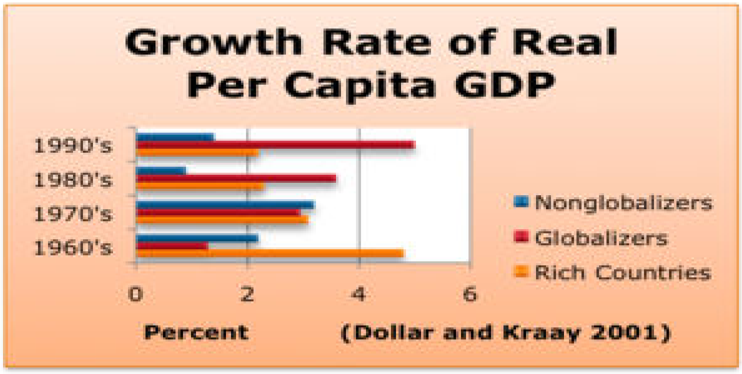

प्रति व्यक्ति रियल जीडीपी की वृद्धि दर

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के (IMF) अनुसार, आर्थिक वैश्वीकरण के विकास लाभ व्यापक रूप से साझा किए जाते हैं। जबकि कई वैश्विक देशों ने असमानता में वृद्धि देखी है, विशेष रूप से चीन में, यह असमानता में वृद्धि घरेलू उदारीकरण, आंतरिक प्रवास पर प्रतिबंध और कृषि नीतियों के बजाय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का परिणाम है।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 6, November 2023 |

मलेशिया की सबसे गरीब पांचवीं आबादी के लिए आय में 5.4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के कारण गरीबी को कम किया गया है। चीन में भी, जहां असमानता एक समस्या बनी हुई है, सबसे गरीब पांचवीं आबादी ने आय में 3.8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि देखी। कई देशों में, डॉलर प्रति दिन गरीबी सीमा से नीचे रहने वालों में गिरावट आई। चीन में यह दर 20 से घटकर 15 प्रतिशत हो गई और बांग्लादेश में यह दर 43 से घटकर 36 प्रतिशत रह गई।

वैश्वीकरण अमीर और वैश्वीकरण राष्ट्रों के बीच प्रति व्यक्ति आय अंतर को कम कर रहे हैं। चीन, भारत और बांग्लादेश, दुनिया के कुछ नए औद्योगिक देशों ने अपने आर्थिक विस्तार के कारण असमानता को बहुत कम कर दिया है।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमरीका और सोवियत संघ में शीत युद्ध छिड़ गया। ये कोई युद्ध नहीं था पर इससे सारा विश्व दो केन्द्रों में बँट गया।

शीत युद्ध के दौरान अमरीका, इंग्लैंड, जर्मनी (पश्चिम), ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, स्पेन एक तरफ थे। ये सभी लोकतांत्रिक देश थे और यहाँ पर खुली अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया गया था। लोगों को व्यापार करने की खुली छूट थी। शेयर बाज़ार मे पैसा लगाने की छूट थी। इन देशों में काफी सारी बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ बनीं। इन कम्पनियों में नयी-नयी रिसर्च होती थी। विश्वविद्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, इंजिनियरी उद्योग, बैंक आदि सभी क्षेत्रों मे जम कर तरक्की हुई। ये सभी देश एक दूसरे देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देते थे। 1945 के बाद से इन सभी देशों ने खूब तरक्की की।

दूसरी तरफ रूस, चीन, म्यांमार, पूर्वी जर्मनी समेत कई और देश थे। ये वे देश थे जहाँ पर समाजवाद की आर्थिक नीति अपनायी गयी थी। यहाँ पर ज्यादातर उद्योगों पर कड़ा सरकारी नियंत्रण होता था। उद्योगो से होने वाले मुनाफे पर सरकारी हक होता था। आम तौर पर ये देश दूसरे लोकतांत्रिक देशों के साथ ज्यादा व्यापर नहीं करते थे। इस तरह की आर्थिक नीति के कारण यहाँ के उद्योगो मे ज्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी। आम लोगो को भी मुनाफा कमाने पर कोई प्रोत्साहन नहीं होता था। इन कारणों से इन देशों में बहुत ज्यादा तरक्की नहीं हुई। 3-अक्टूबर-1990 मे पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी का विलय हुआ। संयुक्त जर्मनी ने तरक्कीशुदा पश्चिमी जर्मनी की तरह खुली अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को अपनाया। फिर 1991 मे सोवियत रूस का विखंडन हुआ। रूस समेत 15 देशों का जन्म हुआ। रूस ने भी समाजवाद को छोड़ के खुली अर्थ्व्यवस्था को अपनाया। चीन ने समाजवाद को पूरी तरह तो नही छोड़ा पर 1970 के अंत से उदार नीतियों को अपनाया और अगले 3 सालों मे बेशुमार तरक्की की। चेकोस्लोवाकिआ भी समाजवादी देश था। 1-जनवरी-1993 को इसका चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया मे विखंडन हुआ। इन देशों ने भी समाजवाद छोड़ कर लोकतंत्र और खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया।[10]

निष्कर्ष

विश्व आर्थिक फ़ॉरम स्विट्ज़रलैंड में स्थित एक ग़ैर-लाभकारी संस्था है। इसका मुख्यालय कोलोग्नी में है। स्विस अधिकारीयों द्वारा इसे एक निजी-सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। इसका मिशन विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ ला कर वैशविक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना है।

इस मंच की स्थापना 1971 में यूरोपियन प्रबन्धन के नाम से जिनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर क्लॉस एम श्वाब द्वारा की गई थी। उस वर्ष यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन प्रोद्योगिकी संगठन के सौजन्य से इस संगठन की पहली बैठक हुई थी। इसमें प्रोफेसर श्वाब ने यूरोपीय व्यवसाय के 444 अधिकारीयों को अमेरिकी प्रबन्धन प्रथाओं से अवगत कराया था। वर्ष 1987 में इसका नाम विश्व आर्थिक फ़ॉरम कर दिया गया और तब से अब तक, प्रतिवर्ष जनवरी महीने में इसके बैठक का आयोजन होता है। प्रारम्भ में इन बैठकों में प्रबन्धन के तरीकों पर चर्चा होती थी। प्रोफेसर ने एक मॉडल बनाया था जिसके अनुसार सफल व्यवसाय वही माना जाता था जिसमें अधिकारी अंशधारी और अपने ग्राहकों के साथ अपने कर्मचारी और समुदाय जिनके बीच व्यस्वसाय चलता है, उसका भी पूरा खयाल रखते हैं। वर्ष 1973 में जब नियत विनिमय दर से विश्व के अनेक देश किनारा करने लगे और अरब-इजराइल युद्ध छिड़ने के कारण इस बैठक का ध्यान आर्थिक और सामाजिक मुद्दों की और मुड़ा और पहली बार राजनीतिज्ञों को इस बैठक के लिए निमंत्रित किया गया। रजनीतज्ञों ने इस बैठक को अनेक बार एक तटस्थ मंच के रूप में भी इस्तेमाल किया। 1988 में ग्रीस और तुर्की ने यहीं पर आपसी यूद्ध को टालने का एलान किया था। 1992 में रंगभेद नीति को पीछे रखते हुए, तत्कालीन दक्षिण अफ़्रीकी राष्ट्रपति और नेल्सन मंडेला, जिन्होंने रंगभेद नीति के विरोध में जीवन पर्यन्त संगर्ष किया था, पहली बार सार्वजनिक रूप से एक साथ देखे गए थे। 1994 में इजराइल और पलेस्टाइन ने भी आपसी सहमति से मसौदे पर मुहर लगाई थी।

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 6, November 2023 |

प्रोफेसर क्लाउस श्वाब 1971 में दावोस में यूरोपीय प्रबंधन फ़ॉरम के उद्घाट्न समारोह में.

सदस्यता

इस संस्था की सदस्यता अनेक स्तर पर होती है और ये स्तर उनकी संस्था के कार्य कलापों में सहभागिता पर निर्भर करती है। सदस्यता के लिए वह कम्पनी जाते हैं जो विश्व भर में अपने उद्योग में अग्रणी होते हैं अथवा किसी भौगोलिक क्षेत्र के प्रगति में अहम भूमिका निभा रहे होते हैं। कुछ विकसित अर्थव्यवस्था में कार्यरत होते हैं या फिर विकसशील अर्थव्यवस्था में।

महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

इस फ़ॉरम की सर्वाधिक चर्चित घटना वार्षिक शीतकालीन बैठक में होती है जिसका आयोजन दावोस नामक स्थान पर किया जाता है। इस आयोजन में भागीदारिता सिर्फ निमंत्रण से होती है और इसकी ख़ास बात यह है की इस छोटे शहर में भागीदार अनौपचारिक परस्पर बातचीत में अनेक समस्याओं का समाधान निकला जाता है। इस बैठक में लगभग २,५०० लोग भाग लेते हैं जिसमें विश्व जगत के, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिज्ञ, गिने चुने बुद्धिजीवी और पत्रकार प्रमुख होते हैं। इसमें उन विषयों पर चर्चा होती है जिस पर विश्व समुदाय की चिंतन अत्यावश्यक मानी जाती है। उदहारण के लिए, २०१२ में इस बैठक में "महान परिवर्तन: नए प्रतिरूप', २०१३ में 'लचीला गतिशीलता', २०१४ में 'विश्व का पुनर्निर्माण-समाज, राजनीति और व्यवसाय के लिए परिणाम' और २०१५ में "नए वैश्विक सन्दर्भ' पर वार्षिक बैठक हुई थी। वर्ष २००७ में इस संस्था ने एक ग्रीष्मकालीन वार्षिक बैठक का आयोजन प्रारम्भ किया। इसका आयोजन चीन के दो सहारों के बीच बारी बारी से किया जाता है। इसमें लगभग १५०० सहभागी आते हैं और वे अधिकतर तेजी से बढ़ते आर्थिक व्यवस्थाएं अर्थात चीन, भारत, रूस, मेक्सिको और ब्राज़ील- से आते हैं। यह वह लोग होते हैं जो अगली पीढ़ी की युवा उद्योगपति अथवा राजनीतिज्ञ जो अपनी सोच और विचारों से दुनिया को अवगत कराते हैं और जो आने वाले समय में विश्व मंच पर महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा। यह संस्था इस बात से भली भांति परिचित है की क्षेत्रीय विचारधारा सम्पूर्ण विश्व के लिए लाभकारी होती है क्योंकि इन विचारों में स्थानीय स्थिति का समावेश होता है। इसे ध्यान में रख कर यह संस्था क्षेत्रीय मीटिंग का भी समय समय पर अफ्रीका, पूर्वी एशिया, लातिनी अमरीका और मध्य पूर्व के देशों में मीटिंग आयोजित करती है। इन सभाओं में नीतिगत व्यापार के नायक, स्थानीय सरकार के नायक और गैर-सरकारी संस्थाओं का मिलन होता है और उस क्षेत्र में उन्नति के लिए आवश्यक कार्य और उसकी दिशा पर चर्चा होती है। यह संस्था ८०० लोगों का युवा विश्व नेता फ़ॉरम का संचालन भी करता है। वर्ष २००७ से संस्था ने सामजिक उद्यमियों को अपने क्षेत्रीय और वार्षिक सम्मलेन में आमंत्रित करना प्रारम्भ किया। इसका औचित्य यह था कि विश्व भर में इस बात की विवेचना हो की किसी भी उन्नति और प्रगति से समाज के सभी वर्गों को एक सा लाभ पहुँचना चाहिए और समाज में होने वाली क्षति को पहले ही भाँपा जा सके। वर्ष २०११ में इस संस्था ने एक संजाल बनाया जिसमें २०-३० वर्ष के आयु के लोगों को मिलाने की पहल की गए जिनमें विश्व को नई दिशा दिखाने की क्षमता थी।

क्लॉस एम श्वैब, संस्थापक एवं कार्यपालक अध्यक्ष, वर्ल्ड इकोनोमिक फ़ॉरम

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 6, November 2023 |

अनुसन्धान रिपोर्ट

यह संस्था प्रबुद्ध मण्डल की भी भूमिका निभाता है और अपने द्वारा किए गए अनुसन्धानों पर आधारित रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है। यह सारी रिपोर्ट अधिकतर प्रतिस्पर्धा, वैश्विक जोखिम और परिदृश्य सोच से सम्बन्धित होती हैं। प्रतिस्पर्धा टीम ने वैश्विक रिपोर्ट में विश्व भर में देशों के बीच प्रतिस्पर्धा के बारे में लिखा था और विश्व भर के सभी देशों में फैले पुरुष और नारी के बीच असमानता पर भी एक रिपोर्ट बनाई थी।

पहल

2002 में विश्व स्वास्थ्य पहल के अन्तर्गत इस संस्था ने सार्वजनिक-निजी क्षेत्रों के सहयोग से एच•आई•वी / एड्स, टुबेरकोलोसिस और मलेरिया जैसी बिमारियों को दूर करने की पहली कोशिश की थी। विश्व शिक्षा पहल के अन्तर्गत भारत, मिश्र और जॉर्डन के सरकारों और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी का मिलन करवा कर कम्प्यूटर और इ-लर्निंग का विस्तार करने का बीड़ा उठाया था। पार्टनरिंग अगेंस्ट करप्शन पहल के तहत 140 कम्पनी ने आपस में मिल कर अपने साथ हुए भ्रष्ट कार्यकलापों को बाँटा और ऐसी परिस्थितयों से निपटने के उपाय पर विचार करने लगे।[11]

संदर्भ

1. /en/about/leadership/members Boards of Executive Directors – Member Countries] . Retrieved on 5 June 2016.
2. ↑ "3 European Powers Say They Will Join China-Led Bank" (अंग्रेज़ी में). मूल से 2 जुलाई 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2 जुलाई 2018.
3. Archived 2019-12-10 at the वेबैक मशीन IMF GDP (Nominal) Data (April 2018)
4. ↑ Archived 2019-12-10 at the वेबैक मशीन IMF GDP (PPP) Data (April 2018)
5. ↑ "Gross domestic product, current prices". International Monetary Fund. International Monetary Fund. October 2015. मूल से 10 दिसंबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 11 October 2015.
6. Babones, Salvatore (15 April 2008). "Studying Globalization: Methodological Issues". प्रकाशित George Ritzer (संपा°). The Blackwell Companion to Globalization. John Wiley & Sons. पृ° 146. आई°ऍस°बी°ऍन° 978-0-470-76642-2.
7. ↑ Joshi, Rakesh Mohan (2009). International Business. Oxford University Press, Incorporated. आई°ऍस°बी°ऍन° 978-0-19-568909-9.
8. ↑ James et al., vols. 1–4 (2007)
9. ↑ https://ncert.nic.in/textbook/pdf/lhps109.pdf
10. The World Economy: Historical Statistics, Angus Maddison
11. ↑ Angus Maddison (2001). The World Economy: A Millennial Perspective Archived 2009-01-23 at the वेबैक मशीन, OECD, Paris

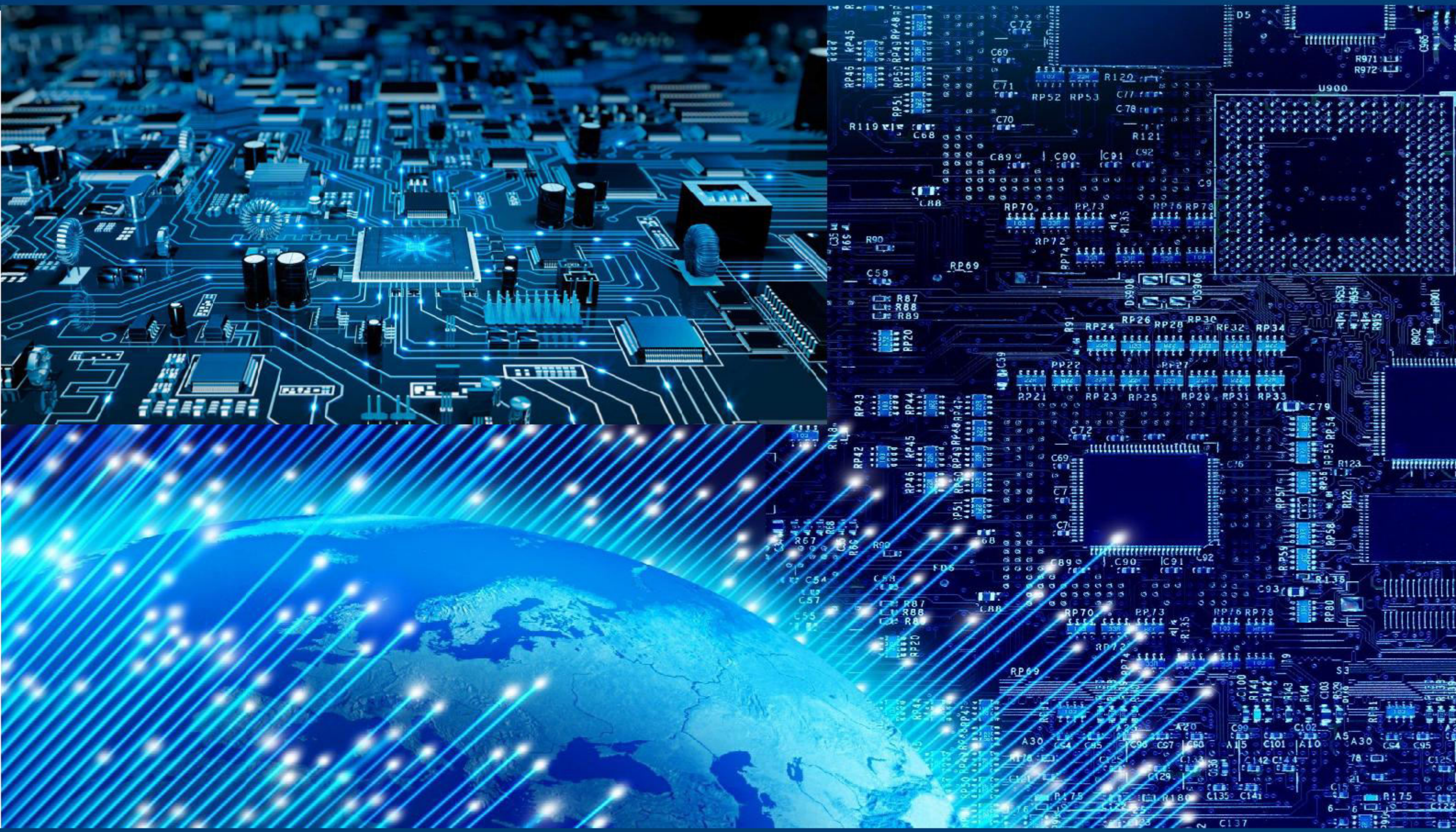

IJARASEM

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

निस्केयर NISCAIR

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |

www.ijarasem.com